

**MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON THE
WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, I move the following motion:-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the unexpired portion of the term of the Committee vice Shri N. Thalavai Sundaram, resigned from the membership of Rajya Sabha and resolves that the House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, one Member from among the Members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

**REPLY TO THE DISCUSSION ON THE STATEMENT OF PRIME MINISTER
RECENT SUMMIT-LEVEL TALKS HELD BETWEEN
INDIA AND PAKISTAN IN AGRA.**

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति जी, 24 जुलाई को भारत-पाक वार्ता के बारे में मैंने एक वक्तव्य दिया था। वक्तव्य एक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित था इसलिए यह स्वामाविक है, सचमुच में आवश्यक था कि उस पर विस्तार से चर्चा होती और भारत-पाक संबंधों के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ फैसले कर सकते।

आगरा वार्ता हमारी दृष्टि से एक सिलसिला था। यह सिलसिला लाहौर से चल रहा है। उस समय भी यह सरकार थी। जितनी तैयारी आगरा के बारे में की गई थी उतनी तैयारी लाहौर वार्ता के पहले हुई थी। लेकिन दोनों में एक अंतर रहा कि बीच में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया। अब पाकिस्तान की सत्ता जिनके हाथों में केंद्रित है, वे लाहौर को हृदय से स्वीकार करना नहीं चाहते। इतना ही नहीं वे शिमला समझौते के बारे में भी एक अनमना रवैया अपनाते हैं। इस सत्ता परिवर्तन के कारण और बीच में कारगिल युद्ध हुआ, एक ऐसी खाई पैदा हो गई, जिसके कारण विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ। हमारे लिए आगरा वार्ता एक कड़ी थी। हमने उसी दृष्टि से तैयारी की थी। हम समझते थे कि पाकिस्तान भी इस बात को समझेगा और कारगिल के युद्ध से जहां सूत्र टूट गया है उस सूत्र को फिर से कायम करेगा।

यह देखकर संतोष हुआ है कि जिन 22 राज्य सभा सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और जिन में विदेश मंत्री जी भी शामिल हैं उन्होंने, वार्ता चलनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया। यह

प्रश्न जरूर उठाया गया था कि आपने एक बार कहा था कि पाकिस्तान में जब तक लोकतंत्र नहीं होगा, हम उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे। प्रणब मुखर्जी जी को स्मरण होगा कि इसी सदन में यह प्रश्न उठा था जब मेरे पूर्व सहयोगी श्री अजीत कुमार पांजा एक सवाल का जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक लोकतंत्र नहीं आता, बातचीत की कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें टोका था और कहा था कि मैं स्थिति स्पष्ट करूं। उस दिन की कार्यवाही का विवरण मेरे पास है। यह पिछले साल 10 अगस्त की बात है।" I think the hon. Prime Minister should say something on this", प्रो. प्रणब मुखर्जी ने कहा था। तब मैंने स्पष्ट किया था, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। "सभापति जी, हमारी इच्छा है कि दुनिया के सारे देशों में लोकतंत्र हो। पड़ोस में हम लोकतंत्रीय देश चाहते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र का तख्ता पलटकर सेना सत्ता संभाल लेती है तो वह एक विरोध का कारण बनता है। हम अपनी नाखुशी प्रकट करते हैं। लेकिन उसको हम शर्त नहीं बनाते, बातचीत करने के लिए। जो जैसा है हम उसी के साथ निपटने के लिए तैयार रहते हैं"। इसलिए यह आलोचना कि पहले हमने मना किया था और फिर हम बातचीत के लिए तैयार हो गए, यह सार्थक आलोचना नहीं है। इसी से जुड़े हुए एक और प्रश्न पर आपत्ति की गयी कि आपने कहा था, जब तक आतंकवादी गतिविधियां बरकरार हैं, आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। हमने बात नहीं की। दो महीने तक बात नहीं की। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग-थलग पड़ गया। केवल हम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जो लोकतंत्र से बंधे हुए हैं, वे पाकिस्तान से दूर हटने लगे और यह मांग बढ़ने लगी - देश के भीतर भी और विशेषकर देश के बाहर - कि भारत को बात करने से इन्कार नहीं करना चाहिए।

जो रेलगाड़ी से बैठकर दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली आने से पहले यहां की दीवारों पर लिखा हुआ एक विज्ञापन देखते होंगे शायदियों के बारे में - "कम से कम मिल तो लें"। मतलब यह कि शादी करें चाहे न करें मगर मुलाकात तो होनी चाहिए। बातचीत होनी चाहिए इसके पक्ष में एक राय है।

हमने युद्धविराम किया। उसे हम संघर्ष विराम कहते हैं। उसका जम्मू काश्मीर में बहुत अच्छा असर हुआ। स्वयं डा. मनमोहन सिंह जी ने यह शिकायत की कि आपने युद्धविराम किया, उसके बाद कदम नहीं उठाया। मतलब यह है कि युद्धविराम करने का काम सही था। बाद में कदम उठाने चाहिए थे लेकिन हमारे सामने जिन्हें बुलाने की समस्या थी वे उस समय आने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें देर हो गयी।

जब पहला युद्धविराम हुआ तो काश्मीर की घाटी में जैसे ईद का वातावरण था। लोग शांति के लिए तरस रहे हैं। खूनखराबे से तंग हैं। वे जिंदगी जीना चाहते हैं। 24 घंटे मौत का साया मंडराता रहे, यह उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन आतंकवादी गुटों ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने भय से, आतंक से, जो शांति की मांग कर रहे थे या जो शांति के पक्ष में बोल रहे थे या युद्धविराम के समर्थक थे, उनको डराया धमकाया, नेताओं को भी धमकियां दीं। इस वातावरण में ऐसा लगा कि युद्धविराम जितना कारगर होना चाहिए था, उतना नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन युद्धविराम की अवधि समाप्त होने वाली थी उसी दिन हमने जनरल मुशर्रफ को बुलाने का निमंत्रण भेजा। ये दोनों घटनाएं अनायास नहीं थीं। इनमें एक तारतम्य था। इसके पीछे एक चिंतन था, एक चिंता थी - किस तरह से जम्मू काश्मीर में शांति आए, किस तरह से बातचीत के लिए रास्ते खुलें। जनरल मुशर्रफ से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई थी लाहौर में। वह भी एक विवाद का विषय बन गया। जनरल मुशर्रफ को इस बात का जवाब देते देते तंग होना पड़ा कि आपने लाहौर

में वाजपेयी से बात क्यों नहीं की थी, वाजपेयी को सलाम करने के लिए आप हवाई अड्डे पर क्यों नहीं आए थे, स्टेशन पर क्यों नहीं आए थे। वह सफाई देते रहे, मगर किसी की समझ में बात आई नहीं। इतना गहरा अविश्वास हो गया था। आज भी है, और इस अविश्वास को हटाना पड़ेगा।

शिखर वार्ता के दौरान एक छोटी सी घटना हुई। मैं नहीं जानता मुझे उसका उल्लेख करना चाहिए या नहीं? यहां काम करने वाली एक महिला ने कहा कि कैन वी ट्रस्ट दिस मैन? क्या इस आदमी पर हम भरोसा कर सकते हैं? उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। वह दलों से जुड़ी नहीं थी। शांति की उपासिका जरूर थीं। भारत के भविष्य के बारे में चिंतित थी। अनायास उसके मुंह से निकल गया, क्या हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। जनरल मुशर्रफ ने इस बात का बहुत बुरा माना। सचमुच में विवाद का एक छोटा सा मुद्दा बना दिया और कहा कि अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? यह बात सच है, हम उन पर भविष्य के लिए विश्वास करना चाहते हैं, इसलिए हमने उन्हें बुलाया है। पाकिस्तान में सत्ता उनके हाथ में है। सत्ता केन्द्रित हो गई है। अब चुनाव की चर्चा हो रही है। देखें चुनाव क्या रूप लेते हैं? लेकिन उस समय तो सारी सत्ता उन्होंने अपने हाथ में समेट ली थी और उसमें उनकी भूमिका निर्णायक हो गई थी। लेकिन यह स्वाभाविक उद्गार था कि क्या हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। कहना नहीं चाहिए था। उन्हें बुरा भी नहीं मानना चाहिए था। भावनाएं कितनी गहरी हैं, यह उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उनको बात बुरी लगी।

मुझे भी एक बात बुरी लगी। जब दिल्ली से लौटने के बाद जनरल मुशर्रफ ने प्रेस सम्मेलन किया और उस प्रेस सम्मेलन में, जो टेलीवाइज किया गया था, उसमें एक पत्रकार ने, उस सभा में पत्रकार ही होना चाहिए, उन्होंने जनरल मुशर्रफ से पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी बार-बार आपको धोखा देता है तो फिर आप उससे बात क्यों करते हैं? एक ही रास्ता है, लड़ाई। जैसे हमने यहां अपनी महिला को बताया कि शिष्टाचार के अंतर्गत यह नहीं आता है। हमने मेहमान बुलाए हैं। अतिथि देवो भवः। अब जैसा भी अतिथि हो। अतिथि भी अपने-अपने कर्मा के अनुसार मिलते हैं। मैं उसके लिए भी दूसरे को दोष नहीं देता। हमारी करनी-धरनी है। लेकिन अविश्वास है। मैं नहीं जानता मुशर्रफ साहब ने उस पत्रकार को समझाया या नहीं। उन्होंने उस समय जो बात कही वह तो समझाने वाली बात थी कि ऐसा मत कहो। वह शायद उन्होंने कहा, कि नहीं, वाजपेयी भले आदमी हैं। पता नहीं मैं कितना भला हूं, कब भला होता हूं, कब बुरा हो जाता हूं। मैं अविश्वास की बात कर रहा था। यह अविश्वास कैसे पैदा हुआ? हमने आगरा में इसलिए रिट्रीट रखी कि आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है। राज्यों के उत्थान-पतन की कहानी आगरा की एक-एक शिला पर अंकित है। वहां सरकारें बदली हैं। परिवार के कलह ने समस्याएं पैदा की हैं, यह भी इतिहासकार जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थियों को पता होगा। वहां ताज महल है। यह प्रेम का स्मारक है। हम समझते थे कि ताज महल की छाया में बैठकर, ताज महल की पृष्ठभूमि में जब बात होगी तो फिर बात ऐसी होगी जो भविष्य के लिए मिलकर काम करने का रास्ता निकालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यह शिकायत की जाती है कि आप ने एजेंडा तय नहीं किया और आप ने उन को बुला लिया। यह बात हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दी है। प्रारंभ से इस बात पर हम बल देते रहे थे कि हमारा जो पुराना एजेंडा है, वह चर्चा के लिए उपस्थित है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। फिर चर्चा के बीच में भी हम ने उन्हें एक छोटासा एजेंडा बनाकर भेजा। मगर जनरल मुशर्रफ के जो संगी-साथी थे, वह कहते थे कि जनरल साहब तय करेंगे। और हम जब उन से बात करते थे तो वह काश्मीर के सिवाय और कोई बात करने के

लिए तैयार नहीं थे। उन की यह मान्यता थी और इसी में गतिरोध के बीज थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी समस्याएं हैं, उन की जड़ काश्मीर है। वह कोर इश्यू था। मेरी जब अलग से उन से बात हुई तो मैं ने उन से कहा कि इस कोर का कोर क्या है? यह काश्मीर का मुद्दा कैसे उठा? समापति जी, डा. कर्ण सिंह बोले हैं। उन्होंने कहा है कि हम ने राज-तिलक कर दिया। जो तिलक लगाकर स्वयं आया हो, उस के लिए राज-तिलक किया जाय, इस का कोई मतलब नहीं है। ... (व्यवधान)...

डा. कर्ण सिंह (दिल्ली) : आप ने स्वस्ति वाचन कर दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन हमारा प्राचीन देश है। यहां अगर पत्थर को भी कोई तिलक लगा दिया जाए तो फिर उस की मान्यता हो जाती है। ... (व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : आप ने यही किया पंडित जी। इस बार यही आप से हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं ने यह नहीं किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि वह तिलक लगाकर आए थे। वह सत्ता अपने हाथ में समेटकर आए थे। हम यह कह सकते थे कि हम आप से बात नहीं करेंगे। विरोधी दल के नेताओं के साथ जो बैठक हुई थी, उस में भी इस की चर्चा चली थी। किसी ने यह नहीं कहा कि आप उन का निमंत्रण वापिस ले लीजिए। आप उन्हें वापिस कर दीजिए। शिखर वार्ता के दौरान उन्होंने जो कुछ किया, वह कूटनीतिक मर्यादा के अनुकूल नहीं था। हम चाहते तो उसी समय तुर्की-ब-तुर्बी जवाब दे सकते थे। फिर शिखर सम्मेलन अलग रह जाता और आपस में सवाल जवाब शुरू हो जाते। मगर मैं ने उन से कहा था कि आप ने जिस तरह से संपादकों को सम्बोधित किया है और जो कुछ आप ने कहा है, उस से शिखर वार्ता का वातावरण दूषित हो गया है। वह फिर भी नहीं समझ रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है। हम ने खण्डन इसलिए नहीं किया कि वह, शिखर वार्ता के लिए जो एक मर्यादा है, उस के प्रतिकूल था। हम उस का पालन कर रहे थे और तात्कालिक प्रचार पर हमारी दृष्टि नहीं थी।

इसलिए उन से लंबी बात हुई। सुषमा जी ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, इसलिए वे नाराज़ हो गए, बात मेरी समझ में नहीं आती। कश्मीर पर तो उनके साथ बात हो ही रही थी लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं दोनों देशों के, पड़ोसियों के बीच, कश्मीर के साथ आइए उन पर भी चर्चा करें। इसीलिए कांफिडेंस बिल्डिंग मेज़र्स का ऐलान किया गया। उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वह भारत और पाक सम्बन्धों के सभी पहलुओं का समावेश करता है। उन्हें वह रास नहीं आया, लेकिन हमने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। लेकिन हमने मर्यादा का पालन किया तो हम कुछ घाटे में रहे। हमारी ओर से मीडिया से और सम्पर्क होना चाहिए था। मीडिया जिस गति से सामग्री चाहती है, जिस तेज़ी से उस सामग्री का वितरण करती है, उसमें वह इतना समय देने के लिए तैयार नहीं थी कि हम, अंत तक वार्ता विफल न हो, इसका प्रयास करते रहें और अगर गतिरोध पैदा होता है तो उसके बारे में भी एक सहमति हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर की समस्या के सामने वह और किसी बात के लिए तैयार नहीं थे।

लेकिन कश्मीर के मामले में जब सवाल उठाए गए कि जो एक तिहाई कश्मीर या आज जो आधा कश्मीर आपके पास है, वह आपके पास कैसे आया है? मैंने उनसे कहा कि आप हथियारों से हर मामला तय करना चाहते हैं। पाकिस्तान प्रारम्भ से ही यही तरीका अपना रहा है।

कश्मीर के लोगों को आपने उस समय आज़ादी नहीं दी कि वे फैसला करते कि उनका भविष्य क्या होगा, वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे या अपने लिए तीसरा रास्ता तय करेंगे, आज आप जनता की राय की बात कर रहे हैं। किस जनता की राय? क्या उस समय राय ली गई थी आपके द्वारा जब आपने कबायली भेज दिए, कबायलियों के पीछे सैनिक भेज दिए? काफी खरी-खरी बातें हुईं। यह ठीक है कि मैं उन सब बातों का उद्घाटन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह धारणा मन में से निकाल दीजिए कि हमने कश्मीर पर बात नहीं की, हम कश्मीर पर बात करने से डरते हैं। हम क्यों डरें? कश्मीर पर हमारा पक्ष प्रबल है, न्यायपूर्ण है। कश्मीर की जनता अपनी इच्छा से भारत के साथ मिली है, संविधान के अनुसार मिली है, यह बंधन अटूट है। मुशर्रफ़ साहब ने एक हिन्दी का शब्द जरूर सीख लिया - अटूट, अटूट बंधन है, आप कहते हैं अटूट बंधन है। हमने कहा आप इसको समझ नहीं सकते हैं। आपके लिए हथियारों का खेल है, आपके लिए यह मज़हब का तकाज़ा है, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता का आधार है। अब मज़हब के आधार पर हम दूसरी बार हिन्दुस्तान को बंटने नहीं देंगे, हिन्दुस्तान का बंटवारा नहीं चाहेंगे। मैंने उनसे कहा कि आपको समझना चाहिए - तीन बार लड़ाई हो चुकी है, क्या परिणाम हुआ, आपको मालूम है। क्या आप फिर लड़ाई चाहते हैं? ये आतंकवादी गतिविधियाँ क्यों? एक दिन ये आतंकवादी गतिविधियाँ आपके लिए अपने घर में मुसीबत पैदा करेंगी। मज़हबी कट्टरवाद, मज़हबी जुनून आज पाकिस्तान में स्वयं अपने लिए एक खतरा बन गया है। सभापति महोदय, आतंकवाद दुधारी तलवार है, इससे समस्याएँ हल नहीं होंगी। हम दोनों की बातचीत में जब काफी समय बीता तो बाहर जो लोग थे, उनको और आडवाणी जी को चिंता हुई कि अंदर क्या हो रहा है? उन्होंने एक आदमी भेजा कि जाकर देखो कि बातचीत हो रही है या ये लोग गप्पें लड़ा रहे हैं। गप्पें लड़ाने का सवाल नहीं था, हम बात कर रहे थे और बात में से बात निकल रही थी और 40 साल से जम्मू-कश्मीर के बारे में मेरे दिल में जो भरा हुआ था, वह मैंने उनके सामने उड़ेल दिया कि आपके लिए यह टैरिटोरियल मामला होगा, मज़हब का मामला होगा, हमारे लिए नहीं है।

उन्होंने मुझ से पूछा कि आप राजनीति में कैसे आए? मैंने कहा कि मैं पत्रकार था और जब डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी परमिट सिस्टम को तोड़कर जम्मू-कश्मीर में प्रविष्ट होने के लिए गए तो मैं पत्रकार होने के नाते उनके साथ था क्योंकि मैं उस यात्रा को कवर कर रहा था। उन्हें माधवपुर की चैक-पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया कि आप आगे जम्मू-कश्मीर में नहीं जा सकते। पंजाब की सरकार ने कहा कि आप जा सकते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर की सरकार ने इजाजत नहीं दी। डा. मुखर्जी गिरफ्तार कर लिए गए। तब डा. मुखर्जी ने मुझे बुलाया और कहा कि "मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, वाजपेयी, तुम वापस जाओ और लोगों से कहो कि देखो मैं बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूँ, जम्मू-कश्मीर भारत का भाग है, यहां परमिट की क्या जरूरत है?" बाद में डा. मुखर्जी की कश्मीर में नज़रबंदी की अवस्था में मृत्यु हो गई।

सभापति महोदय, तिरंगा फहराने के लिए वहां गोलियाँ चली थीं, आज उस सारे इतिहास को खोलने की जरूरत नहीं है। जम्मू-कश्मीर भारत का अंग है। हमारे पाकिस्तानी मित्रों को समझना चाहिए कि यह जेहाद का मामला नहीं है। कैसी जेहाद? किसके खिलाफ जेहाद? अभी कल वहां जो हत्याकांड हुआ है, उसमें औरतें मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं। यह आज़ादी की लड़ाई है या बरबादी का तमाशा है?

सभापति महोदय, जब वार्ता में लगातार इस बात पर जोर दिया गया कि क्रॉस बॉर्डर टैरिज्म को हम स्वीकार नहीं करते तो उन्होंने कहा कि वह तो आजादी की लड़ाई है। फिर ऐसा लगा कि अब बातचीत के लिए कोई आधार नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद पर तो बात करने के लिए तैयार था लेकिन क्रॉस बॉर्डर टैरिज्म पर बात करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इससे वह कटघरे में खड़े होते हैं और आज सारी दुनिया इस बात को जान गई है। आगरा में वार्ता में जो गतिरोध हुआ, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान कटघरे में खड़ा हुआ है। उनकी यह धारणा गलत है कि दुनिया कश्मीर के बारे में सोच रही है। दुनिया यह सोच रही है कि पाकिस्तान कश्मीर के सिवाय कोई और बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? दोनों देशों में संबंध बढ़ सकते हैं, आदान-प्रदान हो सकता है, सांस्कृतिक मेलजोल की गुंजाइश है, नौजवान आ सकते हैं, जा सकते हैं, रास्ते खुल सकते हैं, दुनिया भी यही चाहती है। दुनिया के बहुत से नेताओं से मैंने यह कहा था कि आप वार्ता पर जोर दे रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वार्ता का परिणाम सही न निकले, पाकिस्तान कश्मीर पर अड़ा रहे और हम कश्मीर को देने से इंकार कर दें तो इससे कटुता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन मुझे खुशी है कि वार्ता आगे चली, यह सिलसिला कायम हुआ है। डा. मनमोहन सिंह जी ने यह सवाल उठाया था कि अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैंने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख किया था। डा. साहब ने कहा कि आगरा में संयुक्त घोषणा पत्र तो तैयार नहीं हुआ या कोई वक्तव्य भी नहीं दिया गया। लेकिन मैंने अपने वक्तव्य में जो उल्लेख किया है कि कोई अंडरस्टैंडिंग डवलप हुई थी, तो वह क्या है। मैं समझता हूँ कि विदेश मंत्री महोदय ने इस पर प्रकाश डाला है। अंडरस्टैंडिंग के अनुसार यह निश्चय हुआ है कि वार्ता आगे जारी रहेगी और अपने में एक उपलब्धि है। बहुत से लोगों ने मुझसे आकर कहा था कि एक बातचीत में मामले तय नहीं होंगे, एक बैठक पर्याप्त नहीं होगी, कई बार मिलना पड़ेगा, कम से कम आगे की बैठक की तारीख तय करके आएँ। श्री कुलदीप नैयर ने जो इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं वह बहुत उपयोगी हैं। हमने वहाँ तय किया है कि बातचीत की प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे। मोटे तौर पर बातचीत का फ्रेम वर्क भी तैयार हो गया है। सार्क प्रक्रिया को आगे ले जाने पर सहमति बन गई है। अभी हमने सार्क में भाग लेने से इंकार किया था। हमने कहा कि अगर पाकिस्तान का यही रवैया है कि वह हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में या हर द्विपक्षीय चर्चा में केवल कश्मीर की रट लगाएगा तो फिर बातचीत का कोई अर्थ नहीं होगा, सार्क का सम्मलेन भी व्यर्थ हो जाएगा। उसे आर्थिक बातों तक केन्द्रित रखना चाहिए। सार्क देशों में सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। दुनिया क्षेत्रीय सहयोग की तरफ बढ़ रही है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हर एक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करे मगर ऐसे मिलन स्थल भी ढूँढ़े जहाँ राष्ट्र मिल कर काम कर सकते हैं, अपनी जनता की भलाई के लिए और साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। सार्क सीधा रास्ता है। कोलम्बो में सार्क की एक बैठक में मैं उपस्थित हुआ था। उस समय वहाँ जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात नहीं की कि सार्क के देशों के संबंधों को किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए, उन्हें किस तरह से विस्तार दिया जाए, इसकी चर्चा नहीं की। उन्होंने कश्मीर का अध्याय खोल दिया। लेकिन उसकी जो अध्यक्ष थी, श्रीलंका की राष्ट्रपति, उन्होंने उनको रोका और कहा कि यह द्विपक्षीय मामला है इसकी चर्चा आप यहां मत करिए। मैंने कहा कि हमें डर है फिर यही होगा, वातावरण बिगड़ेगा। अब यह आश्वासन मिला है कि ऐसा नहीं होगा। देखते हैं। अभी बैठक हुई थी हमारे विदेश सचिव की और पाकिस्तान के विदेश सचिव भी थे सार्क में, वहाँ कश्मीर का मामला नहीं उठा। मैं समझता हूँ कि आगे भी यही नीति अपनाई जाएगी, यही व्यवहार किया जाएगा। द्विपक्षीय मामले पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। भारत बातचीत से कभी नहीं

हटा। लेकिन बातचीत के साथ हिंसा या डरा धमका कर, आतंकवाद के भरोसे निर्मम लोगों को बलि का बकरा बनाकर, अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करके बातचीत के लिए विवश किया जाएगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विदेश सचिव मिल चुके हैं। अब विदेश मंत्रियों की मुलाकात होनी है। मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तिथियां अभी तय होना बाकी हैं। हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन बात व्यावहारिक होनी चाहिए, बात दोनों देशों के संबंधों को सुधारने वाली होनी चाहिए, बात सहयोग को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, बात गांठें खोलने के लिए होनी चाहिए, नई गांठें लगाने के लिए नहीं होनी चाहिए। यह अंडरस्टैंडिंग है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसे नहीं मानता। लेकिन जो तय हुआ है उसका मैंने आपके सामने विवरण रखा है। आतंकवाद के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, अभी अफगानिस्तान के बारे में सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री महोदय ने भारत द्वारा उठाये गये कदमों का उल्लेख किया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा वातावरण बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया में काश्मीर की चर्चा नहीं हो रही है, आतंकवाद की हो रही है और उस आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, यह दुनिया की समझ में आ गया है। आखिर जो निर्मम हत्याएँ हो रही हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएँ हो रही हैं, उन्हें कैसे समझाया जायेगा, अपनी कहानी वह आप कह रही है, दुनिया सुन रही है, देख रही है। हमारे पड़ोसी को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए।

डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कहा कि कोई कंसेप्टुअल क्लेरिटी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। यह कंसेप्ट है हमारे सामने। उसकी साफ तस्वीर भी है और मैं नहीं सोचता कि इसमें वलों को लेकर कोई मतभेद होना चाहिए। जहां तक जम्मू-काश्मीर और लद्दाख का सवाल है, वार्ता के लिए जाने से पहले मुझे सर्वदलीय समिति का पूर्ण समर्थन मिला था, मैं उसके लिए आभारी हूँ। जम्मू-काश्मीर का सवाल, यह पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। थोड़ी-बहुत राजनीति तो होती है, हो रही है, हम भी करते थे। अब हमसे कहा जाता है कि आपने शिमला समझौते का विरोध किया था, अब आप समर्थन कर रहे हैं। हमने कहा कि - हाँ, परिस्थिति बदल गई है। जब हमने विरोध किया था तो हम विरोधी दल के कर्तव्य का पालन कर रहे थे और आज हम शासन में बैठे हैं इस धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हमने शिमला समझौते का विरोध इसलिए नहीं किया था कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध होने जा रहे हैं। हमने विरोध इसलिए किया था कि शिमला में अगर भारत चाहता, उस समय का भारत अगर चाहता तो जम्मू-काश्मीर के सवाल को भारत के पक्ष में हमेशा के लिए हल कर सकता था, यह नहीं हुआ। मैं शिमला तक गया था, सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं, सम्मेलन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन अब प्रदर्शन का मौका नहीं है। अब तो संकल्प बांधकर आगे बढ़ने की जरूरत है और इसमें सारे देश की भावनाएँ होनी चाहिए, सारे देश का समर्थन होना चाहिए। इस चर्चा ने कई मुद्दे उजागर किए हैं। जो हमारी कमियाँ थीं, जो हमारी भूलें थीं, उनके बारे में भी हमने सीखा है।...(व्यवधान)...

श्री बालकृष्ण बिरागी : आप भूलें कह कर सुबभा जी की तरफ क्यों देख रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिरागी जी, आप इतना राग रखते हैं कि बिरागी नाम सार्थक नहीं होता।

जहां तक कंसेप्टुअल क्लेरिटी की बात है, मैं डॉ. मनमोहन सिंह जी के भाषण का ही एक अंश सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। "We are in favour of continuing the dialogue with Pakistan to resolve all outstanding issues, even though we must agree that this dialogue cannot make much progress, if Pakistan remains committed to the single-minded pursuit of its sponsoring cross-border terrorism, as it is doing now. ... We must convince Pakistan that its nefarious design will never be allowed to succeed. At the same time, to the people of Pakistan, we must also project a new vision of our common, shared, destiny, that if they forget the logic of "Two-Nation" theory, our two countries can look forward to a very, very bright future". मैं इन शब्दों को डाक्टर मनमोहन सिंह से उधार लेना चाहता हूँ। उनके भाषण से उधार लेकर मैं इन्हें अपने भाषण का अंश बनाना चाहता हूँ। यह हमारी परिकल्पना है। हमारी और आपकी परिकल्पना एक है। छोटी-मोटी बातों पर मतभेद होगा, यह लोकतंत्र में चलता है लेकिन जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, सारा देश एक है, सारी संसद एक है। यह दुनिया ने देखा है और भविष्य में भी देखेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।

RE: FIRE ACCIDENT AT KATPADI IN TAMIL NADU

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Chairman, Sir, in Tamil Nadu about 50 persons died in a fire accident. ...*(Interruptions)*... Sir, more than 50 persons died at Katpadi in Tamil Nadu due to fire. I request the hon. Home Minister to make a statement in the House in regard to that. The Members of this House want to know the reason for the fire. The hon. Home Minister may look into this matter and make a statement in this House today. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra) : Sir, I associate myself with what he has stated. ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu) : Sir, the State Government will take cognizance of it. ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. THIRUNAYUKKARASU: Sir, it is not a question of taking cognizance. It is not petty politics. A pathetic incident took place in Tamil Nadu. Fifty persons died in a fire accident. This House wants to know what happened to the injured persons and what was the reason for the fire. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Sir, there are no politics. Cutting across party lines, Members want to know what happened. ...*(Interruptions)*... Even the Leader of the Opposition would accept it. ...*(Interruptions)*...